डेयरी सहकारिता: दुग्ध क्षेत्र में नवोन्मेश को देते बढ़ावा

आर.एस. सोढ़ी
अध्यक्ष, आईडीए और
पूर्व प्रबंधक निदेशक, अमूल

भारत सरकार ने भारत में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में अत्यंत स्वस्थ सुधार किए हैं।

पिछले साल एक अलग मंत्रालय की स्थापना एक स्वागत योग्य पहल थी, जो भारत की विकास गाथा में सहकारी व्यापार मॉडल के योगदान और अभी तक हासिल की जाने वाली क्षमता को पहचान प्रदान करती है। सहकारिता मंत्रालय के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि की गई। सहकारी समितियों के लिए नई कर राहत की शुरूआत केंद्रीय बजट में की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा है।

समावेशी विकास

भारत में सभी छोटी और बड़ी सहकारी व्यावसायिक इकाइयों की मैपिंग के लिए एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस ग्रिड तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार ने 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.) के कम्प्यूटरीकरण को सक्षम करने के लिए रुपये 2516 करोड के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है।. इन पैक्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि वे छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने वाली बहुउद्देशीय समितियों के रूप में कार्य कर सकें।

भारत सरकार ने किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और उसके लिए लाभकारी रिटर्न प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक विशाल, विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की भी घोषणा की है। पशुपालन क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 3000 करोड़ से बढ़ाकर 4300 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए अलग से 20 लाख करोड़ रुपये का कोष है। सहकारी क्षेत्र को समर्थन देकर सरकार अब देश में अधिक समावेशी विकास की ओर अग्रसर है।

विकासशील बाजार

वित्त वर्ष 2022–23 खत्म हो गया है और इस वर्ष में काफी उतार–चढ़ाव देखने को मिला। दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है क्योंकि दूध की आपूर्ति में कई रुकावटें आ रही हैं। महामारी की शुरुआत के साथ ही उपभोक्ताओं की पसंद विकसित होने लगी। लॉकडाउन युग के बाद की सामान्य स्थिति में एक ओर कुछ प्राथमिकताओं का प्रभाव कम हुआ और दूसरी ओर कुछ रुझान पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए।

ऐसा ही एक चलन जो हमने उपभोक्ताओं के बीच देखा, वह था जलवायु संकट के प्रति बढ़ती जागरूकता। लोग, अब पहले से कहीं अधिक बिगड़ती जलवायु परिस्थितियों के प्रति जागरूक हैं।और पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहते हैं। उपभोक्ताओं की जलवायु संकट के प्रति बढ़ती जागरूकता उन्हें अपनी खरीदारी की आदतों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन ब्रांडों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर रही है जो सक्रिय रूप से स्थिरता के मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं। 2018 में, डब्ल्यू.एम.ओ. ने एक बयान जारी किया जिसमें लिखा था – ''हम जलवायु परिवर्तन को पूरी तरह से समझने वाली पहली पीढ़ी हैं, और शायद आखिरी पीढ़ी जो इसके बारे में कुछ करने में सक्षम है।''

पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक प्रतिफल

एक उद्योग के रूप में डेयरी हमेशा गलत धारणाओं का शिकार रही है। इस क्षेत्र को हमेशा गलत तरीके से पर्यावरणीय क्षति से जोड़ा जाता है जबकि डेयरी उत्पादों का वास्तविक कार्बन फुटप्रिंट आम धारणा की तुलना में काफी कम है। भारत की डेयरी सहकारिताएं नवाचार और संचालन के स्थायी तरीकों को बढ़ावा देने में सबसे आगे रही हैं। और जब मैं स्थिरता षब्द का उपयोग करता हूं, तो मेरा मतलब है चौतरफा सततशीलता–पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता से है ।

इष्टतम लोजिस्टिक्स का सूत्र

रसद और गायों के दूध की गुणवत्ता को अंतिम उपभोक्ता तक बनाए रखने के संबंध में दूध का व्यवसाय सबसे कठिन व्यवसायों में से एक है। सबसे लंबे समय तक, सहकारी और साथ ही निजी खिलाड़ियों ने इष्टतम रसद के कोड को तोड़ दिया है। किसी विशेष क्षेत्र में दूध की खरीद की क्षमता की पहचान करने से लेकर मांग के आकलन तक और ऊर्जा, विनिर्माण और रसद लागत को कम करने के लिए सही उत्पाद मिश्रण को अंतिम रूप देने के लिए दूध खरीद के स्तर पर कई ग्रामीण सहकारी समितियां अब सौर पैनल स्थापना का विकल्प चुन रही हैं। बीएमसी हेतु सौर पैनल न केवल जिला संग्रह केंद्रों पर बिजली की मांग को पूरा करते हैं बल्कि ग्रिड को बेची जाने वाली अतिरिक्त बिजली से भी लाभान्वित होते हैं। विनिर्माण संयंत्रों द्वारा की गई एक अन्य प्रमुख पहल नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में बायो–गैस संयंत्र का विकास है।

प्रसंस्करण के अलावा, दूध और तैयार दूध उत्पादों का परिवहन ईंधन की खपत में महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश डेयरी विनिर्माण संयंत्र अब ''जीरो डिस्चार्ज'' नीति की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले पानी को संयंत्र के भीतर ही पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग किया जाता है। डेयरी अब उपचारित पानी से दीर्घकालिक आकस्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन–हाउस आरओ जल उपचार संयंत्रों में निवेश कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा और हाइड्रोलिक दक्षता में वृद्धि हुई है।

डेयरी अब संचालन के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ रही हैं और एक छोर से दूसरे छोर तक (एंड टू एंड) डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही हैं। ऑपरेशन के हर स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और कागज के उपयोग में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है।

भारत में सभी छोटी और बड़ी सहकारी व्यावसायिक इकाइयों की मैपिंग के लिए एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस ग्रिड तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार ने 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.) के कम्प्यूटरीकरण को सक्षम करने के लिए रुपये 2516 करोड के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है। इन पैक्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि वे छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने वाली बहुउद्देशीय समितियों के रूप में कार्य कर सकें।

अग्रणी तकनीकी हस्तक्षेपों का अंगीकरण

डेयरियां अब व्यापक तस्वीर का विश्लेषण करने और आगामी वर्षों के लिए योजना बनाने के लिए क्षेत्र में संचालन के प्रत्येक स्तर से पशुधन प्रबंधन के लिए डेटा एकत्र करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से, कई डेयरियों ने पशुधन डेटा एकत्र करने के लिए अग्रणी तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए हैं, जो वर्तमान में समय पर किसान सहायता प्रदान करने, भविष्य के लिए योजना बनाने और पशओं के बीच विनाशकारी बीमारियों के प्रकोप को कम करने में मदद करते हैं।

भारत में डेयरी उद्योग भारत में खाद्य सुरक्षा में अत्यधिक योगदान दे रहा है और लाखों उपभोक्ताओं के लिए वहनीय पोषण का स्रोत रहा है। चौतरफा स्थिरता यह सुनिश्चित करने का मंत्र है कि यह क्षेत्र एक बड़े ग्राहक आधार की सेवा करता है और कई और उत्पादकों को सशक्त बनाता है। इन पहलों के साथ, भारतीय डेयरी उद्योग अब भारत में एक लंबे समय तक चलने वाला, सही मायने में प्रोत्साहन देने वाला और पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्र बनाने की उपयुक्त रणनीतियों की ओर बढ़ रहा है।